महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में कार्यरत कर्मचारियों को वेतनमान

3716. **चौधरी हरमोहन सिंह यादव**: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि महानगर टेलीफोन निगम लि. के बनने के दस साल बाद भी इसमें कार्रत अनेक कर्मचारियों को निगम के नियमानुसार वेतनमान नहीं दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा निगम के नियमानुसार वेतनमान दिए जाने हेतु समिति कब गठित की गई थी और इस समिति के सदस्य कौन-कौन थे; और

(घ) गत दो वर्षों के दौरान इस समिति की कितनी बैठकें हुई हैं और इन बैठकों में क्या अंतिम निर्णय लिया गया है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ): (क) महानगर टेलीफोन निगम लि. में निम्नलिखित दो श्रेणियों के कर्मचारी हैं:—

(i) सीधे भर्ती किए गए कर्मचारी (लगभग 70)

(ii) दूरसंचार विभाग से एमटीएनएल में प्रतिनियुक्ति पर माने गए केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी (लगभग 64,000)

उपर्युक्त (i) में उल्लिखित कर्मचारियों को पीएसईयू (आईडीए) वेतनमान पहले ही दे दिए गए हैं।

इसके अतिरिक्त उपर्युक्त (ii) निर्दिष्ट कर्मचारी केन्द्र सरकार के कर्मचारी हैं और उन पर केन्द्र सरकार के वेतनमान एवं सेवा शर्तें लागू होती हैं। उन्हें पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार पहले ही वेतनमान दे दिए गए हैं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) को देखते हुए नहीं होता है।

(ग) महानगर टेलीफोन निगम लि. पर ऐसी कोई समिति गठित किए जाने की आवश्यकता नहीं थी।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) को देखते हुए लागू नहीं होता।

नये डाकघर खोलने के संबंध में लक्ष्य और प्राप्तियां

3717. **चौधरी हरमोहन सिहं यादव**:

श्री नागमणि:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नए डाकघर खोलने के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है;

(ख) यिद नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना हेतु निर्धारित किए गए लक्ष्यों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इन लक्ष्यों को कहां तक प्राप्त किया गया; और

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में किसी अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया है; यदि हां, तो उस अधिकारी के विरुद्ध की गई कार्वाई का ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकावस्थ): (क) और (ख) आठवीं योजनावधि के दौरान समूचे देश में 1440 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर और 650 विभागीय उप डाकघर खोलने का लक्ष्य था। इस लक्ष्य की तुलना में उक्त अवधि के दौरान 1546 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर तथा 466 विभागीय उप डाकघर मंजूर किए गए। विभागीय उपडाकघर खोलने का लक्ष्य प्राप्त करने में कमी रही, क्योंकि विभागीय उपडाकघर खोलने संबंधी जो प्रस्ताव, उनमें निहित पदों के सृजन के अनुमोदनार्थ वित्त मंत्रालय को भेजे गए थे उनमें से वित्त मंत्रालय ने केवल एक प्रस्ताव को ही मंजूरी दी थी।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना में डाकघर खोलने के लिए निर्धारित राज्यवार और लक्ष्य और इस संबंध में हुई अपलब्धि विवरण में दी गई है (नीचे देखिये)।

(घ) उपर्युक्त (क) और (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

आठवी पंचवर्षीय योजना (1992—97) **के दौरान डाकघर खोलने के लिए निर्धारित किए गए सर्किलवार लक्ष्य तथा मंजूर किए गए डाकघर**

क्र. सं.	सर्किल का नाम	आबंटित लक्ष्य		मंजूर किए गए डाक घर	
		अ.वि.*	वि.उ.डा.**	अ.वि.शा.डा.	वि.उ.डा.
1.	आंध्र प्रदेश	42	25	26	28
2.	असम	63	18	63	15
3.	बिहार	183	49	184	25
4.	दिल्ली	1	41	—	25
5.	गुजरात	59	49	59	32
6.	हरियाणा	28	40	34	24
7.	हिमाचल प्रदेश	53	29	128	9
8.	जम्मू एवं कश्मीर	12	8	28	3
9.	कर्नाटक	34	42	39	40
10.	केरल	35	36	48	44
11.	मध्य प्रदेश	113	37	102	28
12.	महाराष्ट्र	163	51	172	62
13.	उत्तर पूर्व	82	18	79	7
14.	उड़ीसा	87	21	94	12
15.	पंजाब	27	19	25	18
16.	राजस्थान	105	43	104	26
17.	तमिलनाडु	30	24	24	19
18.	उत्तर प्रदेश	206	73	244	40
19.	पश्चिम बंगाल	117	27	93	9
	कुल	1440	650	1546	466

*अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर

**विभागीय उपडाघर

Problems of the Extra Departmental Postal workers

3718. SHRI GAYA SINGH:
SHRI GURUDAS DAS GUPTA:

Will the Minister of COMMUNICATIONB be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the problems of the Extra-Departmental Postal workers who operate in the rural hinterland and are charged with the task of delivering postal services even in remote and inaccessible villages;

(b) whether it is a fact that a number of as.surances given by Government including the implementation of Justice Talwar Committee remain unfulfilled; and

(c) if so, the details and Government's reactioin to their demands?